महत्वपूर्ण एवं खास

संकट में सरकारी बैंक

पंजाब नेशनल बैंक में पाए गए भारी-भरकम घोटाले के बाद सरकारी बैंकों की बदहाली का मुद्दा चर्चा में है। इस बात को लेकर आम सहमति बनती जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गहरे संकट का शिकार हैं और वे किसी असाधारण उपाय से ही सुधर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बैंक घोटालों में लगातार तेजी आई है। 2013 में रिजर्व बैंक के तत्कालीन डेप्युटी गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रवर्ती ने बताया था कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटालों का हिस्सा 2004-05 से 2006-07 के बीच 73 फीसद था, जो 2010-11 और 2012-13 में 90 प्रतिशत हो गया। रिजर्व बैंक की फाइनैंशल स्टैबिलटी रिपोर्ट, जून 2017 के अनुसार एक लाख से ऊपर के घोटाले का कुल मूल्य पिछले पांच वर्षों में 9750 करोड़ से बढ़कर 16,770 करोड़ तक पहुंच गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2016-17 में घोटाले की कुल राशि का 86 फीसद हिस्सा लोन से जुड़ा था। बेशक, कई मामले पकड़े भी जा रहे हैं लेकिन घोटालों के साथ बढ़ते एनपीए को देखकर एक राय यह भी सुनने में आ रही है कि क्यों न इन बैंकों को भी निजी हाथों में सौंपकर सारा झंझट ही खत्म कर दिया जाए। पिछले दिनों उद्योग मंडल ऐसोचैम ने कहा कि सरकार को बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे ला देनी चाहिए ताकि सरकारी बैंक भी निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए अपने शेयरधारकों के प्रति पूर्ण जवाबदेही बरत सकें। ऐसोचैम के मुताबिक, सरकार के लिए करदाताओं के पैसे से इन बैंकों को संकट से उबारते रहने की भी एक सीमा है। ऐसी आवाजें कुछ और हलकों से भी उठी हैं, लेकिन मामले को दूसरी तरफ से देखें तो लगता है कि निजीकरण इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि गांवों और छोटे कस्बों तक अपनी पहुंच बढ़ाना निजी बैंकों के अजेंडे पर ही नहीं है। सरकारी बैंकों पर से सरकार का कब्जा हटते ही देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम से कटने के अलावा सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो जाएगी। आज मनरेगा की मजदूरी से लेकर लगभग सारी सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में जा रही है। यह काम सरकारी बैंकों के जरिए ही संभव है। निजी बैंक तो न्यूनतम जमा राशि भी इतनी ज्यादा मांगते हैं कि गरीब तबका उनमें खाता ही नहीं खुलवा सकता।

बीमारी के कारोबार पर पलटवार

एक बात तो मानने की है कि कुछ साल पहले तक भी डॉक्टर को हम सब भगवान माना करते थे। यही कारण है कि डॉक्टर मिलते ही नमस्ते की मुद्रा में हाथ खुद ही जुड़ जाया करते। यदि कोई बीमारी डॉक्टर के बस की ना होती तो डॉक्टर भी हाथ जोड़ लिया करते कि मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ। पर अब दृश्य बदल गया है। जैसे अनाज मंडी, लोहा मंडी, सब्जी मंडी हैं, वैसे ही डॉक्टरों की भी मंडियां हैं। हर शहर में कोई न कोई इलाका ऐसा है जहां नर्सिंग होम और क्लीनिकों की बाढ़ आई हुई है। जिस तरह राजमार्गों पर ढाबे वाले ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिये एक लड़का बिठा देते हैं जो 'आओ जी, आओ जी' करता है, वैसे ही मरीजों को भी खींचने की कवायद शुरू हो गयी है। बीमारी बस की हो या ना हो, बस इलाज चालू हो जाता है और मरीज भर्ती होते ही दिल्ली की टैक्सियों की तरह डॉक्टर के बिल का मीटर भी शुरू हो जाता है। यह और बात है कि किसी भी डॉक्टर के रेट सेम नहीं हैं जो पेशेंट की जेब के अनुसार घटते-बढ़ते भी रहते हैं। टूर एंड ट्रेवल कंपनियों की तरह मरीजों को आकृष्ट करने के लिये पैकेज हैं, डिस्काउंट स्कीम है। मरीज़ों को खुद पर शक होने लगता है कि हस्पताल जा रहे हैं या किसी टूर पर।

शरीफ व सेना के द्वंद्व के बीच पाक

मियां नवाज शरीफ का राजनीतिक कैरियर बहुत दिलचस्प रहा है। पिछले तीन दशकों में तीन मर्तबा वे देश के सर्वोच्च पद पर स्पष्ट बहुमत के साथ विराजमान हो चुके हैं और तीनों बार उन्हें सेना के रचे खेल में अपदस्थ भी होना पड़ा है, आखिरी बार नेशनल अकांउटिबिलिटी ब्यूरो भी इस कृत्य में शामिल रही है। हैरानी इस बात से है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तख्ता पलट सहित अन्य असंवैधानिक कारनामे करने के बावजूद सेना या इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने से ज्यादातर परहेज किया है। पाकिस्तानी सुप्रीमकोर्ट की एक अनूठी खासियत सेना द्वारा किए गए तख्ता पलटों को कानूनी जामा पहनाने की रही है। वहां हुए प्रत्येक सैन्य-विद्रोह को इसने वितर्कों के जरिए 'वक्त की नजाकत के हिसाब से जरूरी' बताते हुए वैध ठहराया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय सत्ता के दुरुपयोग वाले मामलों में सिविलियन राजनेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ निर्णय सुनाने में जरा नहीं झिझक दिखाता वहीं वह बलूचिस्तान, सिंध-कराची और अफगान सीमा से सटे खैबर पख्तूनवा में सेना द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे मानवाधिकार हनन पर उसके खिलाफ कुछ ज्यादा न करने की हिम्मत दिखाकर खुद को जगजाहिर करवाती आई है। पाकिस्तान में सेना को यकीन है कि वह राज-व्यवस्था में एक स्वतंत्र अंग है जो न तो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह है और न ही सुप्रीमकोर्ट के। सेना अब यह संकेत खुलकर दे रही है कि वह नहीं चाहती कि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फिर से सत्ता में वापस आए। उसकी मंशा रही है नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ की महत्वाकांक्षाओं को हवा देकर उनके परिवार में आपसी फूट डलवा दी जाए। जाहिर है कि शाहबाज उस हालात में भी खुश नहीं होंगे यदि आगे चलकर उनके बेटे को सेना के दबाव में प्रधानमंत्री पद पर बिठा जाए। हालांकि नवाज शरीफ हर बार बड़ी जुगत से उक्त चुनौतियों से पार पाते आए हैं। वह सेना के रचे खेल और उसके लाड़ले इमरान खान की तहरीक-ए-पाकिस्तान पार्टी पर भारी रहे हैं। हालांकि फौज चाहती है कि आगामी आम चुनाव में इमरान का दल ज्यादा-से-ज्यादा सीटें जीते ताकि संसद त्रिशंकु रहे। इसी बीच खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के बड़े इलाके में असंतोष काफी गहरा है। बलूच-विद्रोह के नतीजे में हजारों की संख्या में सिविलियन अचानक 'गायब' हो गए हैं। पिछले 7 सालों में 2500 से ज्यादा आम लोगों के अलावा सुरक्षा सेनाओं के 775 जवान और 994 विद्रोही मारे गए हैं। सेना ने वहां बड़े पैमाने पर अभियान चला रखा है, जिसे पूर्व सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ ने ऑपरेशन 'ज़रब-ए-अज़ब' का नाम दिया था। इसमें हवाई हमलों के अलावा तोपखाने का इस्तेमाल भी किया गया है। लगभग दस लाख पश्तून घरबार छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। सीमांत जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हजारों पश्तूनों ने हाल ही में राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा प्रदर्शन किया है। उन्होंने सेना द्वारा जबरदस्ती करने, अवैध और बेलगाम हत्याएं, लोगों को रहस्यमयी ढंग से 'गायब' किए जाने के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरकार सेना ने अभियान रोक दिया है और आर्थिक किल्लत का सामना कर रही सरकार के सामने लाखों बेघरों को बसाने का लगभग नामुमकिन काम पीछे छोड़ दिया है। इस बीच विद्रोही पश्तूनों के संगठन तहरीक-ए-तालिबान ऑफ पाकिस्तान ने स्वात घाटी और अन्य जगहों पर सेना पर नए हमले किए हैं। आने वाले दिनों में जहां दोनों देशों में 'चुनावी बुखार' चढ़ने को है, इसके मद्देनजर भारत को काफी सावधानी से पाकिस्तान से निपटने वाली अपनी योजना उलीकनी होगी। 2017 में सीमापार गोलीबारी की संख्या में वृद्धि करके पाकिस्तानी सेना ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से खुश हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह संदेश दिया है कि आतंकवादियों को दिया जाने वाला उसका समर्थन जारी रहेगा। जम्मू में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमले बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आईएसआई जहां इसके सरगना हाफिज मोहम्मद सईद की सार्वजनिक गतिविधियों को कम करवाते हुए सावधानीपूर्वक अपने पत्ते चलेगी वहीं जैश-ए-मोहम्मद गुट के तंत्र को यथावत रखेगी। सईद की बनिस्बत जैश का कमांडर मौलाना अजहर मसूद ज्यादा हो-हल्ला मचाए बिना काम करता है।

इतिहास ने देखा है किस तरह अपरहण करके कंधार ले जाई गई इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी-814 के यात्रियों की रिहाई के एवज में मसूद अजहर व अन्य कुछ आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी यही अजहर मसूद था। इससे निपटने में हमें तमाम तरह के प्रयास करने होंगे।

प्रतिबंध हल नहीं

बच्चों की सेहत को ध्यान में रखने का दावा करते हुए सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोक सभा में बताया है कि कार्टून चैनल पर जंक फूड के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे. हालांकि बाद में सरकार ने यह भी कहा कि जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध का उनका ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और नौ बड़ी कंपनियां अपनी मर्जी से ऐसा कर रही है. एक रिपोर्ट की मानें तो 5 वर्ष से कम उम्र के 38 फीसदी भारतीय बच्चे 'गंभीर कुपोषण' के शिकार हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मानें तो 13 वर्ष से कम उम्र के 22 फीसद बच्चे मोटापे के भी शिकार हैं. हालांकि, सरकार का दावा है कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से ही ऐसा कदम उठाया गया है, लेकिन सरकार के इन गाइडलाइंस पर कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आई है. दरअसल, ऐसे बहुतेरे सवाल हैं, जो इस प्रतिबंध के बाद जहन में आते हैं. सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विज्ञापनों का प्रसारण, चैनलों और उत्पादन करने वाली कंपनियों दोनों के लिए ही कमाई का जरिया है. इस निर्देश से दोनों को ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. ऐसे में अहम सवाल है कि क्या सरकार ने ऐसे विज्ञापनों के लिए कोई खास आधार तैयार किया है? दरअसल, सरकार को उन विज्ञापनों पर ही रोक लगाने चाहिए, जो निहायत जरूरी लगे. क्योंकि विज्ञापनों का सामान्यीकरण होना चैनलों, कंपनियों और विज्ञापनों में अभिनय करने वालों सभी के लिए ही आर्थिक नुकसान का मामला है. इससे इतर, सरकार का यह कदम उन बच्चों को भी प्रभावित करने वाला है

कमल हासन का पासा

तमिलनाडु की चुनावी राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर गहरा फिल्मी रंग लेने वाली है। साउथ के दो सबसे बड़े फिल्मी सितारे- रजनीकांत और कमल हासन राजनीति के मैदान में मोर्चा बांधते दिख रहे हैं। रजनीकांत ने अभी अपनी पार्टी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कमल हासन ने बुधवार को औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। पार्टी का नाम है मक्कल नीधि मैयम (एमएनएम)यानी जन इंसाफ केंद्र। तमिलनाडु की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वहां की राजनीति काफी लंबे समय से फिल्मी साये में चलती आ रही है। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के ही दिग्गज खिलाड़ी फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं। दूसरा पहलू है तमिलनाडु की राजनीति पर द्रविड़ प्रभाव, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से वहां की राजनीति को शेष भारत के राजनीतिक माहौल से अलग रखने में अहम भूमिका निभाता रहा है। पिछले दो-ढाई दशकों में उत्तर और दक्षिण की दूरी हिंदी फिल्मों और आईपीएल की बदौलत काफी कम हुई है और राजनीति में द्रविड़ प्रभाव भी धुंधला पड़ा है। जो सबसे बड़ा बदलाव तमिलनाडु के राजनीतिक रंगमंच पर दिख रहा है, वह है जयललिता की मृत्यु के बाद उपजा शून्य। हालांकि कमल हासन ने सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाने का संकेत दिया है, जिसके निशाने पर तमिलनाडु की दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां (डी एम के और ए आई ए डी एम के) आ जाती हैं। लेकिन उनकी नजरें ए आई एडी एम के के वोट बैंक पर हैं। यूं ही नहीं वे पार्टी लॉन्च करने से पहले एआईएडीएमके से जुड़े किसी भी शख्स से मिलने नहीं गए। यह भी कह दिया कि रजनीकांत का साथ वे तभी लेना चाहेंगे, जब वे बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखेंगे। पार्टी की घोषणा के दौरान उनके साथ खड़े होने वाले इकलौते बड़े नेता अरविंद केजरीवाल थे। जिस एक अन्य सीएम का संदेश वहां सुनाया गया, वह रहे केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री पी विजयन। साफ है कि कमल हासन भले खुद को मध्यमार्गी कह रहे हों, राजनीति वे लेफ्ट टु द सेंटर मुहावरे की ही करना चाहते हैं। लंबे समय से जातिगत समीकरणों के साथ बंधी तमिलनाडु की सियासत गैर-जातीय कार्यशैली को किस हद तक स्वीकार कर पाती है, यही देखना है।

मजे से खाओ-पीओ और फुट लो

वैसे तो मोदीजी का यह मूल मंत्र है कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। पर वे तो बेचारे अपने प्रियों के खाने पर ही रोक नहीं लगा पा रहे। हर दूसरे दिन वे कहीं न कहीं जीमते हुए मिल जाते हैं। कभी किसी दलित के यहां, कभी किसी आदिवासी के यहां और कभी किसी पार्टी कार्यकर्ता के यहां। टीवी और अखबारों की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। वैसे तो गुजराती में मोटा भाई, बड़े भाई को कहा जाता है, पर कुछ लोग खा-खाकर जिस तरह मुटा रहे हैं, उससे लगता नहीं कि वे मोदीजी के न खाऊंगा, न खाने दूंगा के मंत्र पर चल रहे हैं। डर यही है कि छोटा भाई कहीं मोटा भाई न बन जाए। हालांकि इस पर भाजपा वाले धमका भी सकते हैं कि तुम हमारे नेताजी को बदनाम कर रहे हो। वे तो पार्टी को मुटाने के लिए खाते हैं। आपकी बात सिर-मत्थे जी! वे यह भी कह सकते हैं कि मेरे खाने पर क्यों नजर लगा रहे हैं। युवराज भी यह शिकायत कर सकते हैं कि देखो मोदी राज में भी मैंने सिर्फ अस्सी करोड़ बनाए। नहीं तो आठ सौ करोड़ भी बना सकता था। मुझे कौन रोक लेता। रोकने वालों ने नीरव मोदी को ही कहां रोका। यह ठीक है कि उनके नाम में मोदी लगा है, पर मैं भी मोदी अंकल का कम लाड़ला थोड़े ही हूं। इस पर शौर्य डोवाल शिकायत कर सकते हैं कि हां भैया, मोदी अंकल के लाड़ले तो हम भी बहुत हैं, पर यह बात भी सच है कि वे मोदी नहीं हैं। सो खाओ, पीओ, ऐश करो और फिर इंडिया से फुट लो।

शब्द सामर्थ्य Shabd Samarth

बाएं से दाएं

1. रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकुल, चुनी हुई 3. राजाओं के बैठने का आसन 6. श्रमिक 7. कार्य, काज 9. वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला 10. सहारा, सहायक वस्तु 11. शर्म, लाज, हया 12. मक्खन, माखन 14. श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं 15. चंद्रमा, रजनीश, चांद 18. पुस्तक 20. अवधि, समय 21. तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा 22. सूरत, आकार 23. झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे

1. पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष 2. आग बुझाने की मशीन 3. हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण 4. पराजय, माला 5. मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट 8. चंदन, दक्षिण का एक पर्वत 10. व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य 12. विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव 13. अड़चन, रुकावट 15. जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का 16. बेवकूफ, मूर्ख, अहमक 17. औसत के हिसाब से 18. कृषक 19. अधिक, ज्यादा।

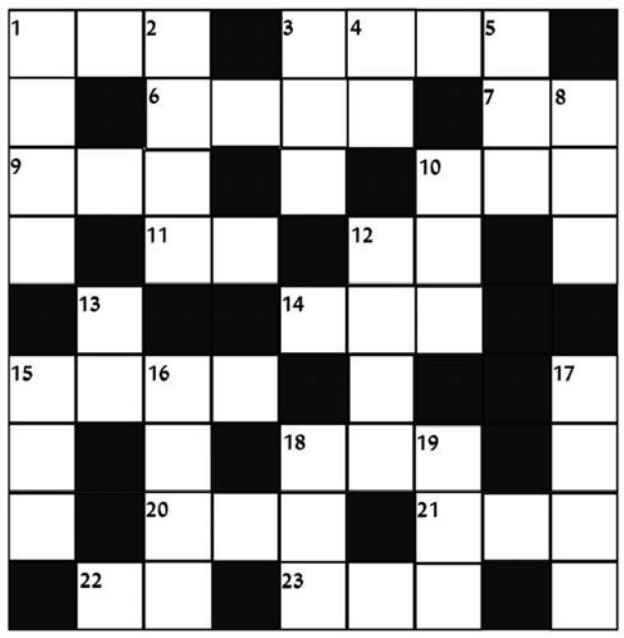

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 31 का हल

ज	ल		आ	वा	जा	ही		
मा		खू	ब		दू	र	स्थ	
ना	दा	न		सा	ग		ल	क्ष्य
	न	ख		त	र	ल		
	वी	रा	न			च	ट	क
	र	ब		आ	ज	क	ल	
			आ	ग		दा	ना	
	अ	ग	र	म	ग	र		क्रो
भा	भी		ती	न			व	ध

सू-दोकू

	8				1		5	
6			8			2		3
	3				2		1	
		3		9		5		4
5			3				9	
		4		2				6
4			2		3		6	
		6				8		7
	2	9	7		6			

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.31 का हल

5	3	9	7	4	8	6	2	1
2	1	6	5	9	3	4	7	6
4	7	8	1	6	2	3	5	9
3	6	1	8	5	9	2	4	7
8	5	2	3	7	4	1	9	6
7	9	4	2	1	6	8	3	5
6	4	7	9	2	1	5	6	3
1	8	5	4	3	7	9	6	2
9	2	3	6	8	5	7	1	4

राशिफल

मेष- यदि आप समय के अनुसार चल रहे हैं तो जरूरत के मुताबिक यह भी महसूस कर रहे होंगे कि जीवन में रिस्क लिए बिना सफलता नहीं मिल सकती।

वृष- आज आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं। एक साथ कई प्रकार के काम हाथ में ले लेने से ऐसा महसूस होना जरूरी भी है।

मिथुन- काफी समय के बाद आज आपको अपने व्यक्तिगत जीवन पर सोच-विचार करने की फुर्सत मिलेगी।

कर्क- आज के दिन आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम तैयार पड़े हैं।

सिंह- भाग्य की एक रेखा आपके जीवन में खींची जा रही है। कभी-कभी ज्यादा परिश्रम करते-करते जब आप बोर हो जाते हैं तो मनोरंजन में खो जाते हैं।

कन्या- अपने जीवन में रचनात्मक कार्य की बजाय सौभाग्य को ही आपने ज्यादा महत्व दिया है।

तुला- अपने स्वास्थ्य को लेकर आज के दिन आपको कुछ जरूरी कदम उठाने आवश्यक हैं।

वृश्चिक- आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव और उतार-चढ़ाव इस दौरान आ रहे हैं।

धनु- आपमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको इन दिनों अपने गृहस्थ जीवन को संवारने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है।

मकर- आज के दिन आप अपने करियर दाम्पत्य जीवन तथा माता पिता सहित सन्तान और परिवार के सदस्यों पर अधिक केन्द्रित हो सकते हैं।

कुंभ- आज आपको अपने मन पर पूरा ही नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी साथी या पड़ोसी के द्वारा कही गई बात पर आप अचानक ही भड़क सकते हैं।

मीन- बुध ग्रह की सहायता से आप अपने कार्यक्षेत्र में इस समय अच्छी ख्याति और यश बटोर सकते हैं।